



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922

No. 266]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्पोर्ट्स शूज (ब्रांडयुक्त तथा ब्रांड रहित दोनों) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करना

फा0सं056/1/2000 डीजीएडी-निर्दिष्ट प्राधिकारी को विश्वस्त स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई है कि चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है)के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्पोर्ट्स शूज का भारत में पाटन किया जा रहा है ।

1. **विचाराधीन उत्पाद:** विचाराधीन उत्पाद स्पोर्ट्स शूज है (जिन्हें इसके बाद संबद्ध सामान भी कहा गया है) जो कि स्पोर्ट्स फुटवियर है जो सीमा शुल्क शीर्ष 6402 से 6405 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तुएं नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित सामान के समान वस्तुएं हैं । यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी तरह बाध्यकारी नहीं है ।

2. **पाटन:** इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिनसे यह पता चलता है कि संबद्ध देश में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य उन कीमतों से काफी अधिक है, जिनपर इन सामानों का भारत को

निर्यात किया गया है जिनसे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है।

3. क्षति एवं कारणात्मक संबंध: विभिन्न मापदण्डों अर्थात् आयातों की मात्रा, और कीमतों में कटौती से प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। पाटित आयातों और उसके परिणामस्वरूप हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध कीमतों में कटौती के प्रभाव से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है।

4. जांच शुरू करना और जांच अवधि: उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 5(4) के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध समानों के आरोपित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1.4.2000 से 30.9.2000 तक की है।

5. सूचना प्रस्तुत करना: भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू विनिर्माता, संबद्ध देश के निर्यातक और भारत के आयातक संगत सूचना प्रश्नावली में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और जो वेबसाइट <http://commin.nic.in/doc> पर उपलब्ध है और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं-

श्री एल.वी. सप्तऋषि
निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

6. नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए संगत प्रश्नावली भेजी गई है ताकि वे जांच आरंभ करने संबंधी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में सूचना दायर कर सकें।

7. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी जांच से संबंधित अपना अनुरोध निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग (उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध और पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय में भी उपलब्ध) से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

8. चूंकि पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध कार्रवाई है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षों को समय सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे।

9. अगोपनीय सारांश: सभी हितबद्ध पक्षों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर प्रदत्त किसी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। यह सूचना नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

10. सार्वजनिक फाइल: नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

11. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल.वी. सप्तर्षि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2000

Subject: Initiation of Anti Dumping investigation concerning imports of Sports Shoes (both branded and un-branded) originating in or exported from People's Republic of China

F. No. 56/1/2000-DGAD.— The Designated Authority has received information from reliable sources that Sports Shoes originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country), is being dumped in India over the last 6 months.

1. **Product under Consideration**: The product under consideration is Sports Shoes (hereinafter also called as subject goods) is sports footwear classified under the Custom Head 6402 to 6405. The goods manufactured by the domestic industry are Like Article to the goods imported from the subject country within the meaning of the Rule 2(d). The classification is further indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation

2. **Dumping:** There is sufficient prima-facie evidence, indicating that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the prices at which it has been exported to India suggesting prima-facie that the subject goods are being dumped into India by the exporters of the subject country.
3. **Injury & Causal Link:** Various parameters viz. volume of imports and price suppression prima-facie indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of the subject goods. The causal link between the dumped imports and its consequential injury is evident from the price undercutting effect.
4. **Initiation and Period of investigation:** The Authority in view of the foregoing paragraphs initiates Anti Dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995.

The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.4.2000 to 30.9.2000.

5. **Submission of information:** The domestic manufacturers of the subject goods in India, the exporters in the subject country and importers in India may submit the relevant information in the form and manner prescribed in the Questionnaire and available at the Website <http://commin.nic.in/doc> and make their views known to :-

Shri L. V. Saptharishi,
The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhawan
New Delhi -110011.

6. The Embassy of the subject country in New Delhi has also been supplied with the questionnaire relevant for the exporters/producers in the subject country so as to enable them to file the information in the prescribed format within the 40 days from the date of publication of this Initiation Notification.

7. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (available at the Website indicated above and also available with the Directorate of Anti-Dumping & Allied Duties) within 40 days from the date of publication of this Notification.
8. Since anti-dumping investigation is time bound, the Designated Authority under no circumstances will grant extension of time to the interested parties for filing their response.
9. **Non-confidential summary:** All interested parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). This information will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and 7(2).
10. **Public File:** In terms of Rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limits set.
11. In case any interested refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority

3185 G1/2020-2

